बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के लिए 8000 करोड़ कर्ज का इंतजाम

वैश्विक निवेशक सम्मेलन में आए निवेशकों को लाभ

- भूमि उपलब्ध होने के बाद बनाई जाएगी महायोजना
- महायोजना के अनुसार विकसित की जाएगी इण्डस्ट्रियल टाउनशिप
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र का होगा सर्वांगीण विकास
- रोजगार का होगा सृजन

लखनऊ। योगी सरकार ने बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन के लिए 8000 करोड़ रुपये के कर्ज का इंतजाम कर दिया है। इसमें पूरे बुन्देलखण्ड क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए लैंड बैंक बनाने के साथ ही अन्य सुविधाओं का विकास होगा।

कैबिनेट ने मंगलवार को औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने बताया कि वैश्विक निवेशक सम्मेलन के जरिए बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 1000 से अधिक एमओयू हस्ताक्षरित किए गए हैं। जिसमें लगभग 3.75 लाख करोड़ का निवेश सम्भावित है। इसके लिए बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है। मंत्री नन्दी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023 में अनुपूरक बजट में नई मांग के माध्यम से प्रदेश में औद्योगिक पार्कों एवं औद्योगिक हब के निर्माण के लिए औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को ऋण के लिए 8000 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया गया है। इसमें से 5000 करोड़ की धनराशि बुन्देलखण्ड औद्योगिक प्राधिकरण के गठन एवं उसके विकास के लिए उपयोग में लाएंगे।